

The Gazette of India

EXTRAORDINARY PART I—Section 1 PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 45A] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1962/CHAITRA 10, 1884

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, ३१ मार्च, १९६२

संख्या २२ निर्यात (५)/६२—भारत सरकार ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में ३० मार्च, १९६१ को एक संकल्प के द्वारा आयात व्यापार नियंत्रण की कार्यविधि विशेष कर आयात नीति निर्धारित करने के बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं तथा आयात लाइसेंस के लिये प्राप्त विभिन्न वर्गों के आवेदन पत्रों को जिस प्रकार निबटाया जाता है, इसकी जांच करने; आयात नियंत्रण की विद्यमान व्यवस्था का संगठन करने; तीसरी पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने के बारे में आवंटन सम्बन्धी प्रश्नों; निर्यात संवर्धन सम्बन्धी विद्यमान उपायों के प्रभाव का पुनरोक्षण करने तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में निर्यात बढ़ाने के लिये आवश्यक उपाय करने के बारे में सिफारिशें करने के लिये श्री ए० रामस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट ५ मार्च, १९६२ को प्रस्तुत कर दी जो प्रकाशित की जा चुकी है। रिपोर्ट में दिये गये प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें तथा उन पर सरकार द्वारा किये गये निर्णय नीचे दिये गये हैं :

२. समिति ने आयात नीति सम्बन्धी उद्देश्यों को स्वीकार कर लिया है जो कि आयात सलाहकार परिषद् के सितम्बर, १९६१ के सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के निम्नलिखित विवरण में दिय गये थे :—

“आयात नियंत्रण की नीति और प्रक्रिया का नियमन इस प्रकार किया जाना है जिससे वह योजना के प्रमुख उद्देश्यों और महत्व के अनुरूप रहे। आयात नियंत्रण को औद्योगिक विकास के एक उपकरण, विदेशी मुद्रा के परिरक्षक तथा निर्यात संवर्धन के साधन के रूप में काम करना चाहिये। उसे देश के औद्योगिक आधार को सुवृद्ध बनाना चाहिये, आर्थिक ढांचे में विविधता लाना चाहिये और स्वतः चालित अर्थ-व्यवस्था वाली स्थिति उत्पन्न करनी चाहिये जिससे कि राष्ट्र अपनी ही शक्ति के बल पर यथासम्भव अधिकसे अधिक आगे बढ़ सके।”

समिति यह मानती है कि संभरण और विकास दोनों के एक दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण उनको अलग नहीं किया जा सकता। सरकार आयात के संभरण बनाम विकास के बारे में समिति की रिपोर्ट के पैराग्राफ ६ से १२ के निर्णयों का ध्यान में रखेगी।

३. समिति ने सुझाव दिया है कि जहां निर्यात होना निश्चित हो सकता हो वहां आवश्यक कच्चे माल तथा सन्तुलन उपकरणों का उपलब्ध कराने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये। तीसरी पंच वर्षीय योजना की रूपरेखा के अन्दर रहते हुए और उपलब्ध विदेशी मुद्रा तथा अन्य आवश्यक सुरक्षाओं के अन्तर्गत सरकार निर्यात के लक्ष्यों और उद्देश्यों से सम्बन्धित औद्योगिक क्षमता का विस्तार करने के प्रस्तावों पर विचार करने को तैयार है तथा पहले से ही विदेशी मुद्रा आवंटित करके सहायता की व्यवस्था कर सकती है जिसमें इसका सुनिश्चय किया जा सके कि निर्यात किया जायगा। सरकार इस प्रकार के प्रस्ताव मांगती रही है और आगे भी मांगती रहेगी। निर्यात संवर्धन में कृषि, उद्योग-विद्या, मत्स्य पालन तथा वन-रोपण का जो महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है, सरकार उसे मानती है।

४. समिति ने सिफारिश की है कि भविष्य में सभी आयात लाइसेंस वार्षिक आधार पर दिये जाने चाहिये और यदि लाइसेंस अवधि के दूसरे भाग में और भी अधिक बृद्ध नीति अपनाना आवश्यक हो तो एक सार्वजनिक नोटिस के द्वारा सभी आयात लाइसेंसों में एक सामान्य प्रतिशत की कमी कर दी जानी चाहिये। सरकार ने इस सिफारिश पर सावधानी से विचार किया है। चूंकि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति अब भी कठिन बनी हुई है और सभी आयातों में सामान्य प्रतिशत की कमी कर देने से उपलब्ध विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल प्राथमिकता पाने वाली विभिन्न वस्तुओं पर उचित रूप से लागू नहीं हो सकेगा, इसलिये जैसा कि समिति का विचार है, वार्षिक लाइसेंस देना व्यावहारिक नहीं होगा। फिर भी सरकार ने निश्चय किया है कि आगे से लाइसेंस के सभी आवेदन पत्र वार्षिक आधार पर होने चाहिये। जहां तक सम्भव हो सकेगा लाइसेंस वार्षिक आधार पर जारी किये जायेंगे तथा बाकी के लिये अर्द्धवार्षिक लाइसेंस जारी किये जायेंगे। सरकार की आशा है कि कुल में से काफी लाइसेंस वार्षिक आधार पर जारी किये जायेंगे। जब वार्षिक लाइसेंस जारी किये जायेंगे तो उनके लिये निम्नलिखित शर्तें होंगी :—

- (१) वर्ष के प्रथमाद्ध में लाइसेंस के अंकित मूल्य के केवल ५० प्रतिशत का इस्तेमाल किया जा सकता है ; और
- (२) मूल्य की शेष राशि का इस्तेमाल केवल लाइसेंस देने वाले अधिकारी द्वारा लाइसेंस पर पृष्ठांकन किये जाने पर मूल्य में किये गये परिवर्तनों तथा अन्य शर्तों के अधीन, जो सरकार निश्चित करे, किया जा सकेगा।

५. कुछ अन्य प्रक्रिया संबंधी मामलों के बारे में सरकार ने समिति की निम्नलिखित सभी सिफारिशों स्वीकार कर ली हैं :—

- (१) वास्तविक उपयोक्ताओं और पुराने आयातकों के लाइसेंसों के मामले में प्रारंभिक वैधता की अवधि एक वर्ष तथा बन्धित ऋण के बदले में जारी किये गये सी० जी०/एच० ६० पी० लाइसेंसों के अलावा सी० जी०/एच० ६० पी० लाइसेंसों की अवधि दो वर्ष होनी चाहिये।
- (२) बन्धित ऋण के बदले में जारी किये गये लाइसेंसों को छोड़कर पुनः वैधीकरण का अधिकार क्षेत्रीय लाइसेंस अधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिये।

- (३) पुराने आयातकों के लाइसेंसों की वैधता की अवधि सामान्यतः नहीं बढ़ाई जानी चाहिये । किन्तु विशेष परिस्थितियों में ऐसे लाइसेंसों को तीन महीने के लिये बढ़ाया जा सकता है ।
- (४) लघु उद्योग समिति की सिफारिशों तथा मुख्यालयों में स्पष्टीकरणों/अपीलों को निबटाने के लिये प्रबन्ध किये जाने चाहिये ।
- (५) आयात के मुख्य नियंत्रक की तदर्थ समिति में विकास स्कन्ध के संबंधित टेक्निकल अधिकारियों और अधिक पूर्णतः के साथ प्रतिनिधित्व होना चाहिये ।
- (६) अनुसूचित उद्योगों से संबंधित आवेदनों के निबटाने में शीघ्रता करने के लिये अन्तर्निदेशालय बैठकों का अधिक इस्तेमाल किया जाना चाहिये ।
- (७) प्रत्येक लाइसेंस अवधि की अधिकतम राशि सम्बन्धी सूचना सभी लाइसेंस अधिकारियों के पास लाइसेंस अवधि आरम्भ होने से ठीक पहले पहुँचानी चाहिये ।
- (८) विभिन्न वर्गों के आयात लाइसेंसों के आवेदन पत्रों की जांच उन्हें सरल करने की दृष्टि से की जानी चाहिये ।

समिति ने ये सिफारिशें भी की हैं :—

- (क) लाइसेंसधारी से संभरण उपलब्ध न होने के बारे में प्रमाण लिये बिना ही निवेदन करने पर वास्तविक उपयोक्ताओं के लाइसेंसों का छः मास के लिये तथा सी० जी०/एच० ई० पी० के लाइसेंसों का एक वर्ष के लिये पुनः वैधीकरण किया जाना चाहिये ।
- (ख) आई० बी० सी० संख्या तीन वार्षिक लाइसेंस अवधियों तक के लिये वैध मानी जानी चाहिये ।
- (ग) जहाँ तक अनुसूचित उद्योगों का संबंध है, आयात के मुख्य नियंत्रक को अनिवार्यता का पता लगाने के लिये लाइसेंस अवधि के प्रारम्भ में ही सामान्य कसौटी निश्चित कर देनी चाहिये जिससे उद्योग निदेशकों का अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करने में मार्ग-दर्शन हो सके ।

जहाँ तक पुनः वैधीकरण की अवधि का सम्बन्ध है सिफारिश (क) स्वीकार कर ली गई है किन्तु पुनः वैधीकरण वर्तमान शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जायेगा । सिफारिश संख्या (ख) के बारे में सरकार का विचार यह है कि आई० बी० सी० अवधि केवल दो वार्षिक अवधियों तक वैध समझी जानी चाहिये । जहाँ तक सिफारिश (ग) का संबंध है, आयात के मुख्य नियंत्रक प्रत्येक लाइसेंस अवधि के प्रारम्भ में ही उद्योग निदेशकों के लिये सामान्य निदेश जारी करते हैं जिससे अनिवार्यता का पता लगाने के लिये कसौटी निश्चित की जा सके । किन्तु इस बारे में उद्योग निदेशकों के परमर्श से यह जांच की जायगी कि इस प्रणाली को किस प्रकार और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है ।

६. लाइसेंस देने के काम की विकेंद्रीकरण समिति की नीचे लिखी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है :—

- (१) मुख्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित एक सामान्य नीति के अधीन पाकिस्तान के ताजे फलों के लिये लाइसेंस देने के काम को विकेंद्रित किया जाय ;

(२) अखबारी कागज के अतिरिक्त मुद्रण उद्योग की जरूरत की चीजों (जैसे मुद्रण मशीनें आदि) से सम्बद्ध काम मुख्य आयात नियंत्रक को एक तदर्थ समिति द्वारा उसी ढंग से किया जाय जैसे इसी प्रकार की अन्य चीजों के बारे में किया जाता है ।

(३) जांच-पड़ताल के जिन मामलों पर इस समय अखबारी प्रकोष्ठ द्वारा कार्रवाई की जा रही है, भविष्य में उन सभी पर 'जांच विभाग' द्वारा आवश्यकतानुसार अखबारों के रजिस्ट्रार की सलाह से कार्रवाई की जा सकेगी ।

अखबारी कागज, ग्रीज और लुब्रीकेण्टों के लिये लाइसेंस देने के काम का भी समिति विकेंद्रीकरण करना चाहती थी, किन्तु इस समय सरकार इसकी प्रणाली यथावत बनाये रखना चाहती है ।

७. सरकार समिति की इस बात से सहमत है कि कोटा अधिकारों के हस्तांतरण अर्थात् नये आयातकों को मान्यता देने और कोटा देने का सारा काम विकेंद्रित कर दिया जाय । यह सिफारिश इस वर्ष पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर दी जायगी । समिति की सिफारिश के अनुसार सरकार ने आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक के मुख्य कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में जन सम्पर्क अधिकारियों को नियुक्त करने का भी निश्चय कर लिया है ।

८. पुराने आयातकों को लाइसेंस देने और थोड़े मूल्य के लाइसेंसों के सम्बन्ध में जो नीति और प्रक्रिया इस समय चालू है समिति सामान्यतः उसमें सन्तुष्ट है किन्तु उसमें कुछ सुधारों का सुझाव दिया है । सरकार सिद्धान्त रूप में इन्हें स्वीकार करती है ।

९. विकास स्कन्ध द्वारा देश में प्राप्त कच्चे माल, पुर्जें और उपकरण, आयात नियंत्रण संगठन, आयात नियंत्रण के मामलों की जांच और आई० सी० टी० तथा आई० टी० सी० वर्गीकरण के सम्बन्ध में जो एक वार्षिक रजिस्टर प्रकाशित किया जाता है समिति ने उसके सम्बन्ध में कुछ सिफारिशों की हैं । ये इस समय विचाराधीन हैं । समिति का यह विचार कि तदर्थ लाइसेंस देना कम किया जाय, सिद्धान्ततः स्वीकार्य है और तदर्थ लाइसेंसों के अधीन वस्तुओं के विषय में कार्रवाई करने की प्रक्रिया निकालने के लिये प्रयत्न किये जायेंगे । अपीलों का काम निबटाने के लिये क्षेत्रीय लाइसेंस कार्यालयों में अनुभागों और मुख्यालय में एक कानूनी प्रकोष्ठ स्थापित करने के सम्बन्ध में समिति की सिफारिश भी सरकार ने स्वीकार कर ली है ।

१०. समिति ने कहा है कि चौथी योजना के अन्त तक देश के निर्यात को दुगुना करने के लिये असाधारण प्रयत्न करने की आवश्यकता है । केवल परम्परागत वस्तुओं के लिये ही नहीं अपितु निर्यात करने योग्य सभी वस्तुओं को निर्यात बाजारों में पहुंचाने के लिये सारे देश को एक विशेष आन्दोलन करना पड़ेगा । समिति ने महसूस किया है कि देश ने अभी निर्यात की समस्या का केवल एक छोर ही छुआ है । इसने सिफारिश की है कि निर्यात के लिये एक वार्षिक योजना तैयार की जाय जिसमें उद्योगवार तथा जिनसवार लक्ष्य निर्धारित किये जायें और इसके लिये सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में विकास योजनाओं और प्रायोजनाओं की व्यवस्था की जाय । समिति ने निर्यात वाले उद्योगों को सहायता देने और निर्यात के लिये किये गये वादों का सख्ती से पालन कराने पर समान रूप से जोर दिया है । इस संबंध में राज्य सरकारों और व्यापारी समुदाय के कार्य का महत्व बताते हुए समिति ने कहा है कि कुछ चुनी हुई रियायतों, राजकोषीय राहतों और अन्य प्रोत्साहनों के द्वारा निर्यात के बन्धों को लाभप्रद बनाने का दायित्व भी सरकार पर है । अब तक जो प्रोत्साहन दिये गये हैं,

समिति के मत से ये केवल साधारण हैं और मच तो यह है कि वे अक्सर बेकार साबित होते हैं और इसके लिये सहायता और प्रोत्साहनों की अधिक साहसपूर्ण नीति की जरूरत है। निर्यात संवर्धन निदेशालय के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के साथ-साथ, समिति ने सुझाव दिया है कि केन्द्र में कोई प्रभावशाली समन्वयकारी व्यवस्था की जानी चाहिये और उन निदेशालय में नीति-प्रकोष्ठ भी स्थापित किया जाना चाहिये।

११. समिति ने निर्यात के लिये नीचे लिखी सहायता और प्रोत्साहन देने की सिफारिश की है :—

- (१) अत्यधिक प्रभावशाली सहायताओं में से एक यह भी है कि उद्योगों की आयात द्वारा अधिकाधिक कच्चे माल का निर्धारण किया जाय। यदि देश में निर्धारित विदेशी मुद्रा के कारण सीमान्त आवश्यकता के कच्चे माल, हिस्से-पुर्जे और उपकरणों का आयात करना सम्भव न हो तो और अधिक सहायता पाने के लिये ऐसे विशेष मामलों की मित्र देशों के सामने रखा जाय।
- (२) इस प्रकार के अतिरिक्त आयातों का वित्त-पोषण करने के लिये आयात-निर्यात स्थिरीकरण, निधि नाम की एक परिक्रामी निधि स्थापित की जाय, जिसका प्रशासन एक स्वायत्त निकाय द्वारा किया जाय।
- (३) भारतीय निर्यात उद्योगों द्वारा काम आने वाले कच्चे मालों के आयातों के लिये, रुपया भुगतान के आधार पर वित्त-पोषण करने वाली विदेशी फर्मों के प्रस्तावों पर विचार किया जाना चाहिये।
- (४) आयात में छूट देने की एक तीन-स्तरीय प्रणाली चालू की जाय, अर्थात् :—
 - (क) मूलभूत निर्यातों पर हुए लाभ में कर की छूट ;
 - (ख) निर्यात विकास निधि स्थापित करने में निर्यातकों को समर्थ बनाने के लिये कर की छूट, और
 - (ग) अतिरिक्त निर्यातों पर कर संबंधी विशेष छूट।
- (५) मुद्रा प्रतिधारण का आश्रय लेना आवश्यक नहीं है। इस के बदले निर्यात संवर्धन की वर्तमान योजनाओं के क्षेत्र को सभी निर्यातों को समाविष्ट करने योग्य बना देना चाहिये। निर्यात की वस्तुओं का निर्माण करने के लिये अधिकाधिक प्रकार के कच्चे माल, पुर्जे और उपकरणों के आयात के लिये निर्यातक/निर्माता को प्रोत्साहन लाइसेंस का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिये और यदि आयात की गई जित्सी की किसी विशेष उद्योग को जरूरत नहीं है तो उन्हें किसी साथी उद्योग को बेष देने की अनुमति होनी चाहिये। ये रियायतें निर्यातकों के साथ साथ निर्माताओं को भी मिलनी चाहिये, यद्यपि केवल निर्यातक (या निर्माता जो कि सामान को स्वयं प्रयोग नहीं करना चाहता) का हक निर्माता/निर्यातक के हक का केवल दो-तिहाई ही होगा।
- (६) जहाजों पर लगी गई सभी वस्तुओं पर रेलों को २५ प्र० श० की एक सामान्य छूट देनी चाहिये।
- (७) कुछ निर्यात उद्योगों के सामने आने वाली विशेष कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में चाय, कॉफी और मछली उत्पादनों के मामलों का उल्लेख किया गया है।

- (८) सभी या कम से कम निर्यात की अधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं पर तटकर की वापसी करने के लिये एक सारणी तैयार की जानी चाहिये । और वापसी की मांग करने वाले निर्यातक से केवल निर्यात का सबूत और विदेशी मुद्रा की ठीक राशि की पावती प्रस्तुत करानी चाहिये ।
- (९) निर्यात की लागत में शामिल होने वाले बिक्री-कर की छूट देने का दायित्व भी केन्द्रीय सरकार को लेना चाहिये और उदाहरण के लिये २ प्रतिशत की एक समान छूट दी जानी चाहिये ।
- (१०) आयात शुल्कों, उत्पादन शुल्कों और बिक्री करों की वापसी किसी एक केन्द्रीय स्थान, जैसे सीमा-शुल्क के कलक्टर के यहाँ से होनी चाहिये ।
- (११) व्यापारियों और उद्योगपतियों को देश में उपभोग करने के लिये बेचे जाने वाले उत्पादनों पर एक छोटा सा उपकर लगाने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये और उस लाभ को निर्यात को सहायता के लिये प्रयोग किया जाना चाहिये । समिति अनिवार्य निर्यातों के पक्ष में नहीं है ।
- (१२) जब कि सरकार निर्यात संवर्धन के विभिन्न रूपों का काम करने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम की आवश्यकता के सम्बन्ध में सहमत है, तो समिति द्वारा सुझाये गये विशेष उपायों का भी विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता है और इस संबंध में सरकार के निर्णय शीघ्र ही घोषित कर दिये जायेंगे ।
- (१३) समिति ने सरकार द्वारा विचार करने के लिये अनेक अन्य सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत की हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने, विदेश स्थित भारतीय व्यापारियों से सम्पर्क रखने, व्यापार सदन की भूमिका, पर्यटन, रुपया भुगतान, व्यवस्था, राज्य व्यापार, वस्तु-विनिमय व्यापार, किस्म नियंत्रण, निर्यातकों को नाम देशिका, विदेशों में भारत को धाणिज्यिक प्रतिनिधित्व, निर्यात जोखिम गारण्टी, आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता, उक्त कार्यालय, निर्यात-संवर्धन निदेशालय और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के कर्मचारियों की पारस्परिक अदला बदली की आवश्यकता, आदि के सम्बन्ध में हैं । इन मामलों पर समिति के सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं और सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की सलाह से व्यावहारिक सीमा तक समुचित कार्यवाही की जायगी ।
- (१४) समिति द्वारा जो मूल्यवान काम किया गया है सरकार उस की हार्दिक प्रशंसा करती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को दे दी जाय ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सभी की जानकारी के लिये इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

डी० एस० जोशी,
अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार ।